

राकेश कुमार वर्मा

बनाम

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

(2025 की दीवानी अपील संख्या 2282)

08 अप्रैल 2025

[दीपांकर दत्ता* और मनमोहन, न्यायामूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

यह मुद्दा उठा कि क्या नियुक्ति पत्र के विशिष्ट खंडों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों द्वारा पटना और दिल्ली की न्यायालयों में दीवानी वाद दायर किए जा सकते थे, जिसमें कहा गया था कि मुंबई की न्यायालयों के पास अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा और उनके बीच विवादों का फैसला करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

निर्णय-सार

अनुबंध अधिनियम, 1872 -धारा 28-कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए समझौते-न्यायालयों की विशेष अधिकारिता-उत्तरदाता बैंक द्वारा दो कर्मचारियों की नियुक्ति, एक पटना में और दूसरा दिल्ली में और नियुक्ति पत्र में विशेष क्षेत्राधिकार खंड कि मुंबई में न्यायालयों को किसी भी विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा-धोखाधड़ी और कदाचार के आरोपों के कारण दोनों कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति-- पटना में नियुक्त कर्मचारी ने पटना में दीवानी वाद दायर किया - इसके बाद, बैंक ने आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका दायर कर वाद को खारिज करने की मांग की, क्योंकि मुंबई के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार था, न कि उस न्यायालय का जहाँ वाद दायर किया गया था-विचारण न्यायालय ने उसी को खारिज कर दिया-बैंक द्वारा इसके खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन, पटना उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई-दिल्ली में नियुक्त कर्मचारी द्वारा बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले वाद के मामले में, दिल्ली में विचारण न्यायालय ने माना कि क्षेत्राधिकार खंड दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं

करता है-बैंक द्वारा पुनरीक्षण आवेदन, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-शुद्धता:

अभिनिर्धारित: बैंक ने अपने दावे में उचित ठहराया कि मुंबई में वाद दायर किए जाने चाहिए थे-सेवा अनुबंध और विशेष क्षेत्राधिकार खंड के अवलोकन पर, पटना उच्च न्यायालय ने एक ठोस कानूनी राय दी, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने में गलती की-एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड वैध होने के लिए, यह धारा 28 के अनुरूप होना चाहिए , इसे किसी भी पक्ष को अनुबंध से संबंधित कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए; विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया न्यायालय इस तरह के क्षेत्राधिकार के लिए सक्षम होना चाहिए; और पक्षों को या तो निहित रूप से या स्पष्ट रूप से न्यायालयों के एक विशिष्ट समूह को क्षेत्राधिकार प्रदान करना चाहिए-अनुबंध करने वाले पक्षों को नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते की शर्तों पर समायोजित किया गया था, जिसमें मुंबई में न्यायालयों को विशेष रूप से विवाद समाधान के स्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया था-जब तक कि एक रोजगार अनुबंध किसी भी लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए-कानून सभी अनुबंधों को समान सम्मान के साथ मानता है और जब तक कि एक अनुबंध किसी भी दूषित कारकों से पीड़ित साबित नहीं होता है, नियम और शर्तों को पक्षों की सापेक्ष ताकत और कमजोरी की परवाह किए बिना लागू किया जाना चाहिए-विशेष क्षेत्राधिकार खंड कर्मचारी के कानूनी दावे को आगे बढ़ाने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि केवल कर्मचारी को अकेले मुंबई की न्यायालयों के समक्ष उन दावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित करता है-मुंबई में न्यायालयों के पास क्षेत्राधिकार था-अनुबंध में उल्लिखित खंड में "अनन्य" शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था-दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया गया और पटना उच्च न्यायालय ने उस हद तक पुष्टि की- पटना उच्च न्यायालय ने विधि के बिंदु पर बैंक के पक्ष में सही निर्णय देते हुए भी, आदेश VII, नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत बैंक की याचिका को खारिज करने की अनुमति देकर एक मौलिक त्रुटि की। पटना उच्च न्यायालय के लिए उचित प्रक्रिया यह होती कि वह आदेश 7, नियम 10 के तहत विचारण न्यायालय को याचिका वापस करने का निर्देश देता ताकि इसे मुंबई की

सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके-दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908-
आदेश 7 नियम 11. [कंडिकार्ये 18, 21, 23, 26, 29-33, 38]

न्याय दृष्टांत

स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड [2013] 7
एससीआर 581 (2013) 9 एससीसी 32-पर अवलंबित।

विशाल गुसा बनाम एल एंड टी फाइनेंस, 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली
2806-अस्वीकृत।

हकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड [1971] 3 एस. सी. आर. 314:(1971
) 1 एससीसी 286; ग्लोब ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बनाम त्रिवेणी इंग.वर्क्स (1983) 4
एस. सी. सी. 707; ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्रा.लिमिटेड बनाम ए. पी. एजेंसियां,
सलेम [1989] 2 एस. सी. आर. 1 (1989) 2 एस. सी. सी. 163; पटेल रोडवेज
लिमिटेड बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कं. [1991] 3 एससीआर 391 (1991) 4 एससीसी
270; एंजाइल इंसुलेशन बनाम डेवी एशमोर इंडिया लिमिटेड [1995] 3 एससीआर
443:(1995) 4 एस. सी. सी. 153; न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कं. बनाम यूनाइटेड
इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [2004] पूरक 1 एस. सी. आर. 623 (2004) 4
एस. सी. सी. 677; श्री शुभलक्ष्मी फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड बनाम चांद मल
बरदिया [2005] 2 एस. सी. आर. 1138:(2005) 10 एससीसी 704;
राजस्थान एसईबी बनाम सार्वभौमिक पेट्रोल रसायन लिमिटेड [2009] 1 एस. सी.
आर. 138:(2009) 3 एससीसी 107; ए. वी. एम. सेल्स कार्पोरेशन बनाम
अनुराधा केमिकल्स (पी) लिमिटेड [2012] 1 एससीआर 318:(2012) 2 एस.
सी. सी. 325-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

अनुबंध अधिनियम, 1872; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908।

मुख्य शब्दों की सूची

अभियोग की अस्वीकृति; शिकायत की वापसी; न्यायालयों का विशेष क्षेत्राधिकार;
कानूनी कार्यवाही के प्रतिबंध में समझौता; सेवा का अनुबंध; रोजगार समझौता;
विवाद समाधान की स्थिति; क्षेत्राधिकार को छोड़कर; कर्मचारी का कानूनी दावा
करने का अधिकार; नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते में विशेष क्षेत्राधिकार खंड; सेवा
की समाप्ति; धोखाधड़ी और कदाचार के आरोप; पुनरीक्षण आवेदन।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की दीवानी अपील संख्या 2282

2020 के सी.आर. संख्या 23 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से
के साथ

2025 की दीवानी अपील संख्या 2286

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता; ऋषभ राज जैन; सुश्री काजल शर्मा; ग्रिजेश कुमार;
सुश्री अमिती गुप्ता; उदयन जैन; सोनल जैन; संदीप एस देशमुख; वात्सल्य विज्ञा;
प्रदीप कुमार त्रिपाठी।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता:

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता; जी. एस. चतुर्वेदी; शांतनु चतुर्वेदी; सुश्री प्रियंका
त्यागी सूर्यकांत; ऋषभ राज जैन; सुश्री काजल शर्मा; ग्रिजेश कुमार; सुश्री अमिती
गुप्ता; उदयन जैन; सोनल जैन।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति

चुनौती

- 1 . मुख्य अपील¹ में, राकेश ने पटना उच्च न्यायालय² के दिनांक 25 जनवरी, 2022 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर एक दीवानी

1 दीवानी अपील संख्या 2282/2025

2 पटना उच्च न्यायालय, इसके बाद

पुनरीक्षण आवेदन³ को स्वीकार किया गया है।

- 2 . संबद्ध अपील⁴ में, एच.डी.एफ.सी. बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय⁵ के दिनांक 12 नवंबर, 2011 के निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें उसके दीवानी पुनरीक्षण आवेदन⁶ को खारिज कर दिया गया था।

तथ्य

3. मुख्य अपील तथ्यों के एक सरल समूह पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं:
- I. 24 जुलाई, 2002 के पत्र के माध्यम से, एचडीएफसी बैंक ने राकेश को थोक बैंकिंग संचालन में कार्यकारी, लेनदेन बैंकिंग समूह (संचालन) के पद पर नियुक्त किया। इसके अनुसार, राकेश एकजीबीशन रोड, पटना में थोक बैंकिंग संचालन में अपनी सेवा में शामिल हुए।
 - II. राकेश के नियुक्ति पत्र में एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड था, जो इस प्रकार है:
“इस नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नियम और शर्तें बैंक में आपके रोजगार पर लागू होने वाली सेवा शर्तें हैं और इससे संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में बॉम्बे न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।”
 - III. राकेश की सेवा 28 अगस्त, 2016 को धोखाधड़ी और कदाचार के आरोपों के कारण समाप्त कर दी गई थी।
 - IV. इससे आहत होकर राकेश ने पटना के अवर-न्यायाधीश-1 की न्यायालय में

3 2020 की दीवानी पुनरीक्षण संख्या 23

4 दीवानी अपील संख्या 2286/2025

5 दिल्ली उच्च न्यायालय, इसके बाद

6 2021 की दीवानी पुनरीक्षण याचिका संख्या 79

एक दीवानी वाद⁷ दायर किया, जिसमें निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई:

“क) यह घोषणा की जाती है कि दिनांक 28.06.2016 का बर्खास्तगी पत्र जो इसके साथ संलग्न अनुलग्नक-सी है, अवैध, मनमाना, अनुचित, अनुचित, असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण है, विधि के विरुद्ध और क्षेत्राधिकार से बाहर है, और तथ्यों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इसे अमान्य घोषित किया जाए और रद्द किया जाए।

ख) अंतरिम निषेधाज्ञा के तहत प्रतिवादियों को दिनांक 28.06.2016 के बर्खास्तगी पत्र को प्रभावी करने से रोका जाए और उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे वादी को सभी परिणामी लाभों सहित सेवा में तत्काल बहाल करें।

ग) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे वादी को तत्काल सेवा में बहाल करें और उन्हें वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करें, जिसमें 18% प्रति वर्ष का ब्याज भी शामिल है।”

V. समन प्राप्त होने पर, एचडीएफसी बैंक ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908⁸ के आदेश VII, नियम 11 के तहत इस आधार पर शिकायत को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की कि यह मुंबई की न्यायालयें हैं जिनके पास क्षेत्राधिकार है न कि वह न्यायालय जहाँ वाद दायर किया गया था।

VI. एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा दायर याचिका को विचारण न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

VII. उक्त याचिका खारिज होने से असंतुष्ट, एचडीएफसी बैंक ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो तब से सफल रहा है।

4. संबंधित अपील भी इसी तरह के तथ्यों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं:

7 2017 की स्वत्व वाद संख्या 212

8 दीवानी प्रक्रिया संहिता

- I. दीप्ति को भगवान कृष्ण बैंक में लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका 2009 में एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया था। 23 मार्च, 2009 के रोजगार समझौते के अनुसार, दीप्ति को जनकपुरी, दिल्ली में खुदरा बैंकिंग शाखा में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस समझौते में राकेश के मामले की तरह ही एक समान अनन्य क्षेत्राधिकार खंड भी शामिल था। इसके अनुसार, पक्षों के बीच किसी भी विवाद के कारण कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होने पर, उसका निपटारा मुंबई की सक्षम न्यायालय में किया जाना था।
- II. दीप्ति की सेवा 31 मई, 2017 को धोखाधड़ी और कदाचार के आरोपों के कारण भी समाप्त कर दी गई थी।
- III. इससे व्यथित होकर, दीप्ति ने वरीय असैनिक न्यायाधीश, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली की न्यायालय में एक दीवानी वाद⁹ दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई:

" क) 31.05.2017 दिनांकित समाप्ति पत्र को अमान्य घोषित करें क्योंकि यह अवैध है और इसे अभिखंडित कर दें;
ख) प्रतिवादी को वापस मजदूरी और सेवाओं की निरंतरता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ वादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दें।"

- IV. एच.डी.एफ.सी. बैंक ने अपना लिखित बयान दाखिल करते हुए कहा कि कार्रवाई का कारण पूरी तरह से मुंबई में उत्पन्न हुआ और दिल्ली की न्यायालयों का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- V. विचारण न्यायालय ने 17 अप्रैल, 2021 के आदेश के माध्यम से प्रारंभिक मुद्दे का जवाब दिया कि क्या उसके पास वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है और यह

अभिनिर्धारित किया कि अनन्य क्षेत्राधिकार खंड दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है।

- VI. विचारण न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट, एचडीएफसी बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खारिज कर दिया गया है।

आक्षेपित आदेश

- 5 . दीवानी पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के बाद प्रमुख अपील में आक्षेपित निर्णय ने इस आधार पर अनुमति दी कि पटना में विचारण न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार खंड के आलोक में क्षेत्राधिकार नहीं है और ऐसा खंड सेवा की समाप्ति के मामलों में भी काम करेगा। *स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*¹⁰ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अवलंबन करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि सामान्य सिद्धांत यह है कि वाद किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ कार्रवाई के कारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न होता है, हालांकि, जब तत्काल मामले में ऐसा खंड मौजूद होता है, तो क्षेत्राधिकार उस स्थान पर न्यायालयों के पास होगा जिस पर पक्षों द्वारा और उनके बीच स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है, यानी तत्काल मामले में बॉम्बे की न्यायालयें।
6. संबंधित अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश ने दीवानी पुनरीक्षण आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दीप्ति दिल्ली में रह रही थी, रोहिणी, दिल्ली में काम कर रही थी और समाप्ति पत्र उसे दिल्ली में दिया गया था और रोजगार समझौते में विशेष क्षेत्राधिकार खंड ने दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को नहीं हटाया था।

विद्वान न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ के *विशाल गुप्ता बनाम एल एंड टी फाइनेंस* मामले में निर्णय पर अवलंबन किया। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एचडीएफसी बैंक को अनुतोष देने से इनकार कर दिया।

प्रश्न

7. इन अपीलों पर निर्णय के लिए उठने वाला विशुद्ध कानूनी प्रश्न यह है कि, क्या राकेश और दीप्ति द्वारा क्रमशः पटना और दिल्ली की न्यायालयों में दीवानी वाद दायर किए जा सकते थे, जबकि नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि मुंबई की न्यायालयों को अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा?

विक्षेपण और कारण

- 8 . इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी दावों की सराहना करने के लिए आगे बढ़ें, लागू कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना उचित होगा।
9. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872¹² की धारा 28 में आदेश दिया गया है:

28. कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए समझौते, अमान्य- प्रत्येक समझौता, -

(क) जिसके द्वारा कोई भी पक्ष सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी भी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित है,

11 2009 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 2806

12 अनुबंध अधिनियम

या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है; या

(ख) जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है, या किसी भी पक्ष को किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त कर देता है, ताकि किसी भी पक्ष को अपने अधिकारों को लागू करने से रोका जा सके, उस हद तक अमान्य है।

....."

10. दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 20 का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

20. जहाँ प्रतिवादी रहते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, वहां स्थापित किए जाने वाले अन्य वाद। सीमाओं के अधीन-उपर्युक्त, प्रत्येक वाद स्थानीय सीमाओं के भीतर एक न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता -

(क) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहाँ एक से अधिक हैं, वाद के शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; या

(ख) प्रतिवादियों में से कोई भी, जहाँ वाद शुरू होने के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की अनुमति दी जाती है, या प्रतिवादी जो नहीं रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत

रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है,
ऐसी संस्था में सहमत होते हैं; या

(ग) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।

स्पष्टीकरण- किसी निगम को भारत में स्थित अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में व्यवसाय करते हुए माना जाएगा, या किसी ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी वाद-विवाद के संबंध में, जहाँ उसका कोई अधीनस्थ कार्यालय भी है, उस स्थान पर व्यवसाय करते हुए माना जाएगा।

11. यह अनगिनत बार है जब इस न्यायालय को अनुबंधों में ऐसे खंड से निपटना पड़ा है जो विवादों के निपटारे को केवल एक पक्ष द्वारा चुने गए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तक सीमित करता है, न कि दूसरे पक्ष¹³ द्वारा अस्वीकृत न्यायालय तक। दरअसल, मुकदमों की शुरुआत और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत, जहाँ पक्षकारों ने आपसी सहमति से किसी विशेष स्थान की न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है, इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किए गए हैं जो पूरी तरह से सुसंगत हैं और जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। इन अपीलों पर उचित निर्णय के लिए इनमें से कुछ निर्णयों का अवलोकन अनुचित नहीं होगा।

12. न्यायालय ने **हकम सिंह बनाम गैमन (भारत) लिमिटेड**¹⁴ में अभिनिर्धारित किया कि:

4. दीवानी प्रक्रिया संहिता संपूर्ण रूप से मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू होती है। मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, किसी निर्णय को दाखिल करने हेतु कार्यवाही पर विचार करने के लिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा

13 अनन्य क्षेत्राधिकार खंड

14 (1971) 1 एससीसी 286

नियंत्रित होता है। समझौते के खंड 13 के अनुसार, पक्षों के बीच स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि अनुबंध को संबंधित पक्षों द्वारा बॉम्बे शहर में संपन्न माना जाएगा। किसी भी स्थिति में उत्तरदाताओं का अपना प्रमुख कार्यालय बॉम्बे में है और वे उत्तरदायी थे। बॉम्बे की न्यायालयों में वाद किए जाने वाले निविदा की शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाई के कारण के संबंध में। यह पक्षकारों के लिए समझौते द्वारा किसी न्यायालय को अपने समझौते के क्षेत्राधिकार द्वारा प्रदान करने के लिए खुला नहीं है जो वह करता है। संहिता के तहत स्वामित्व नहीं है। लेकिन जहाँ दो या दो से अधिक न्यायालयों को दीवानी प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार के तहत पक्षकारों के बीच एक समझौते पर वाद चलाने या कार्यवाही करने के लिए कहा गया है कि उनके बीच विवाद का वाद चलाया जाएगा। ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है। ऐसा समझौता अनुबंध अधिनियम के धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है।

(जोर दिया गया)

13. एक दशक बाद, एक अन्य समन्वय पीठ को *ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम त्रिवेनी इंजीनियरिंग वर्क्स*⁵ में इसी तरह के अनन्य क्षेत्राधिकार खंड से निपटने का अवसर मिला। कंडिका 3 में एक वाक्य कानून के सार को दर्शाता है, जो इस प्रकार है:

3. यह अब स्थापित कानून है कि पक्षों के लिए किसी समझौते द्वारा किसी न्यायालय को ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान करना संभव नहीं है जो उसके पास अन्यथा न हो। लेकिन यदि एक से अधिक न्यायालय हों जहाँ वाद दायर किया जा सकता है, तो पक्षों को किसी विशेष न्यायालय का चयन करने और अन्य न्यायालयों को अस्वीकार करने का अधिकार है। यह चयन उन दावों के संबंध में किया जा सकता है जो एक पक्ष के पास अनुबंध के तहत दूसरे पक्ष के विरुद्ध हो सकते हैं।.....

14. कुछ वर्षों बाद *ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम ए.पी. एर्जेंसीज, सलेम*⁶ के

15 (1983) 4 एससीसी 707

मामले में निर्णय आया। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

21. उपरोक्त निर्णयों से यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहाँ ऐसा बहिष्करण खंड मौजूद है, वहाँ यह देखना प्रासंगिक है कि क्या अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का बहिष्करण हुआ है। जब खंड स्पष्ट, असंदिग्ध और विशिष्ट हो, तो अनुबंध की स्वीकृत अवधारणाएँ पक्षों को बाध्य करेंगी और जब तक कि समान अधिकार का अभाव सिद्ध न हो जाए, तब तक अन्य न्यायालयों को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। बहिष्करण खंड की व्याख्या के संबंध में, जब "अकेला", "केवल", "अनन्य" और इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। ऐसे शब्दों के बिना भी, उपयुक्त मामलों में, "एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस" (एक का उल्लेख दूसरे का बहिष्कार है) का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। उपयुक्त मामला क्या है, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले में, एक बात का उल्लेख दूसरी बात के बहिष्कार का संकेत दे सकता है। जब किसी अनुबंध में विशिष्ट क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट किया जाता है, तो अन्य सभी को इसके संचालन से बाहर रखने का इरादा माना जा सकता है। इसलिए इसकी उचित व्याख्या की जानी चाहिए।

15. **स्वास्तिक गैसेस (पी) लिमिटेड** (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने किसी भी अनुबंध में अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के आशय को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:

32. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें समझौते में क्षेत्राधिकार खंड के प्रभाव को देखना होगा, जिसमें यह प्रावधान है कि समझौता कोलकाता की न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। यह सच है कि समझौते में क्षेत्राधिकार खंड का प्रावधान करते समय "अकेले", "केवल", "अनन्य" या "अनन्य क्षेत्राधिकार" जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन

हमारी राय में यह निर्णायक नहीं है और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समझौते में खंड 18 के होने से पक्षों का इरादा स्पष्ट है कि कोलकाता की न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा, जिसका अर्थ है कि केवल कोलकाता की न्यायालयों का ही क्षेत्राधिकार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समझौते के खंड 18 जैसे क्षेत्राधिकार खंड की व्याख्या के लिए, किसी एक बात का स्पष्ट उल्लेख, अन्य बातों का बहिष्कार है का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि इसके विपरीत कोई संकेत नहीं है। इस कानूनी सिद्धांत का अर्थ है कि एक का उल्लेख दूसरे का बहिष्कार है। समझौते में यह प्रावधान करके कि यह कोलकाता की न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, पक्षकारों ने अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर कर दिया है। जहाँ अनुबंध में किसी विशेष स्थान की न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है और ऐसी न्यायालयों को मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, तो हमारा मानना है कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्षकारों का इरादा अन्य सभी न्यायालयों को बाहर करने का था। इस प्रकार का खंड अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा खंड न तो कानून द्वारा निषिद्ध है और न ही यह लोक नीति के विरुद्ध है। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है।

(जोर दिया गया)

16. इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय भी हैं जिनमें इसी प्रकार के अनन्य क्षेत्राधिकार खंडों को बरकरार रखा गया है। *पटेल रोडवेज लिमिटेड बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी*,¹⁷ *एंगिले इंसुलेशनस बनाम डेवी एशमोर इंडिया लिमिटेड*,¹⁸ *न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*,¹⁹ *श्री सुभलक्ष्मी फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड*

17(1991) 4 एससीसी 270

18(1995) 4 एससीसी 153

19(2004) 4 एस. सी. सी. 677

बनाम चंद मल बरडिया,²⁰ राजस्थान एसईबी बनाम यूनिवर्सल पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड²¹ और ए.वी.एम. सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम अनुराधा केमिकल्स (पी) लिमिटेड²²

के निर्णय इनमें से कुछ हैं जो इस संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

17. अनन्य क्षेत्राधिकार खंड को कैसे पढ़ा और समझा जाना चाहिए, यह मुद्दा अब कोई नया मुद्दा नहीं रह गया है।
18. उपरोक्त निर्णयों का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेष अधिकार क्षेत्र खंड वैध होने के लिए, यह (क) अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् यह किसी भी पक्ष को अनुबंध से संबंधित कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, (ख) जिस न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है, वह सर्वप्रथम ऐसे अधिकार क्षेत्र के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात् जिस न्यायालय के पास वैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे अनुबंध के माध्यम से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है, और अंत में, (ग) पक्षकारों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के एक विशिष्ट समूह को निहित रूप से या स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। इन तीनों शर्तों/मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
19. *स्वास्तिक गैसेस (पी) लिमिटेड* (उपरोक्त) का निर्णय वर्तमान तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है, और चूंकि यह एक बड़े पीठ का निर्णय है, इसलिए यह हम पर बाध्यकारी है।
20. हालांकि, इस न्यायालय के उपरोक्त उल्लिखित किसी भी पूर्व निर्णय में सेवा/रोजगार अनुबंध पर विचार नहीं किया गया। राकेश और दीप्ति के विद्वान अधिवक्ता श्री देशमुख और श्री चतुर्वेदी के अनुसार, *विशाल गुप्ता* (उपरोक्त) मामले में दिया गया निर्णय

20(2005) 10 एस. सी. सी. 704

21(2009) 3 एस. सी. सी. 107

22(2012) 2 एस. सी. सी. 315

सेवा/रोजगार अनुबंधों के संबंध में कानूनी स्थिति को सही ढंग से स्पष्ट करता है। इसलिए, यह न्यायालय विद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए दूरदर्शी दृष्टिकोण और व्यावहारिक विचार को स्वीकार करने पर विचार कर सकता है। यह तर्क दिया गया है कि शक्तिशाली शेर (नियोक्ता) और डरपोक खरगोश (कर्मचारी) के बीच असमान लड़ाई में, जहाँ पासा शुरू से ही कर्मचारी के खिलाफ भारी रूप से झुका हुआ है, कर्मचारी को नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते में उल्लिखित शहर (मुंबई) की न्यायालयों तक सीमित करके न्याय की उसकी खोज में और कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। (नियोक्ता) और डरपोक खरगोश (कर्मचारी), जहाँ कर्मचारी के खिलाफ शुरुआत से ही पासा भारी मात्रा में भरा हुआ है, उसे नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते में उल्लिखित शहर (मुंबई) की न्यायालयों में पेश करके न्याय के लिए उसकी खोज में कोई और प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

21. इस स्तर पर, इन अपीलों से संबंधित कानूनी स्थिति पर एक संक्षिप्त नज़र डालना उचित होगा। सार्वजनिक सेवा और निजी नियोक्ता के साथ सेवा अनुबंध में बहुत बड़ा अंतर है। सरकारी सेवा की उत्पत्ति संविदात्मक होती है। हर मामले में प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद, सरकारी कर्मचारी को एक दर्जा प्राप्त हो जाता है और उसके अधिकार और दायित्व अब दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित नहीं होते, बल्कि कानून या वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अनुबंध की तुलना में अधिक दर्जे की होती है। किसी विवाद के मामले में, सरकारी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा किसी विशेष स्थान की न्यायालयों में वाद चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14, 16 और 21 इसमें बाधा बन सकते हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में सेवा रोजगार अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होती है, जो पक्षों के बीच *आपसी सहमति* से तय की जाती है। किसी भी अन्य अनुबंध की तरह, रोजगार अनुबंध में भी, एक संपन्न

अनुबंध के लिए कम से कम दो पक्षों का अस्तित्व आवश्यक होता है जिनके आपसी अधिकार और दायित्व होते हैं। एक बार अनुबंध संपन्न हो जाने पर, यह सर्वविदित है कि पक्षों के ऐसे अधिकार और दायित्व उसकी शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चूंकि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच पहले से ही सहमति होती है, इसलिए उनके इरादों को अनुबंध (यहाँ नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौता) से समझा जा सकता है और इसे देखकर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुबंध करने वाले पक्ष नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते की शर्तों पर *सहमत* थे, जिसमें मुंबई की न्यायालयों को विशेष रूप से विवाद समाधान स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

22. आजकल, निजी क्षेत्र अंतिम छोर तक लोगों तक पहुँचने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में व्यक्तियों को नियुक्त करता है। इसलिए, निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं के लिए पंजीकृत कार्यालय से दूर-दराज के स्थानों पर वाद लड़ना संभव नहीं हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहिष्करण खंडों को शामिल करने का यह भारी कारण है। राकेश और दीप्ति ने नियुक्ति पत्र/रोजगार समझौते के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने-अपने पदों पर शामिल होकर इसकी शर्तों पर काम किया, वे संभवतः इस दूसरे विचार पर अनुबंध से बच नहीं सकते थे कि इसमें निहित अवधि उनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है।
23. जब तक कोई रोजगार अनुबंध प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी लागू कानून, जैसे कि अनुबंध अधिनियम या दीवानी प्रक्रिया संहिता, में आम तौर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह बात निर्विवाद है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप का दायरा काफी सीमित है।
24. राकेश और दीप्ति की ओर से यह तर्क कि ऊपर उल्लिखित निर्णय सेवा अनुबंध के मामले में लागू नहीं होंगे, हमें प्रभावित नहीं करता। अनुबंध – चाहे वह वाणिज्यिक हो, बीमा हो, बिक्री हो, सेवा हो, आदि – अंततः एक अनुबंध ही होता है। यह एक कानूनी

रूप से बाध्यकारी समझौता है, चाहे इसमें शामिल पक्ष या उनकी आपसी ताकत कुछ भी हो। रोजगार अनुबंधों के लिए इस आधार पर भेदभाव करना कि एक शक्तिशाली शेर और एक डरपोक खरगोश अनुबंध करने वाले पक्ष हैं, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि अधिकार और दायित्व पक्षों की स्थिति, शक्ति या प्रभाव पर निर्भर नहीं होते। अनुबंधों को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के समान रूप से माना जाना चाहिए। यह तथ्य कि एक पक्ष अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली है (शक्तिशाली शेर) और दूसरा अधिक कमजोर (डरपोक खरगोश) अनुबंध सिद्धांतों के अनुप्रयोग में अपवाद या भेदभाव करने का औचित्य नहीं देता।

25. हम इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि असमान सौदेबाजी शक्ति केवल व्यक्तिगत सेवा अनुबंधों तक ही सीमित नहीं है। व्यापार, वाणिज्य या अचल संपत्ति जैसे कई क्षेत्रों में, अनुबंधों में ऐसे पक्ष शामिल हो सकते हैं जिनकी ताकत, संसाधन या सौदेबाजी शक्ति का स्तर भिन्न-भिन्न हो। उदाहरण के तौर पर, हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ बड़े बिल्डर अपने द्वारा सौंपे गए विकास कार्य के एक हिस्से को उप-ठेकेदारों को सौंप देते हैं। ऐसे अनुबंधों में भी एक शक्तिशाली शेर और एक कमजोर मेमना शामिल होते हैं, हालांकि शेर डरपोक नहीं होता। पक्षों की स्थिति के आधार पर, यदि पक्ष अनुबंध में किसी ऐसी शर्त को लागू करने का प्रयास करता है जिसे पक्ष दमनकारी मानता है, या पक्ष अपने किसी भी दायित्व को निभाने से इनकार करता है, तो पक्ष अनुबंध के उल्लंघन के लिए वाद का सामना करता है। यदि पक्ष अपने किसी दायित्व को बोझिल समझकर पूरा करने से इनकार करता है, तो पक्ष परिणामों से बच नहीं सकता।
26. कानून सभी अनुबंधों को समान सम्मान के साथ मानता है और जब तक कि कोई अनुबंध किसी भी दूषित करने वाले कारक से पीड़ित साबित नहीं होता है, तब तक नियमों और शर्तों को पक्षों की सापेक्ष ताकत और कमजोरी की परवाह किए बिना

लागू किया जाना चाहिए।

27. इस प्रकार, हम *विशाल गुप्ता* (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को मंजूरी देने में असमर्थ हैं।
28. तत्काल अपीलों में विचाराधीन सेवा अनुबंध और विशेष क्षेत्राधिकार खंड के अवलोकन पर, हम आश्चर्य हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने तथ्यों के संदर्भ में एक ठोस कानूनी राय दी है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने *विशाल गुप्ता* (उपरोक्त) में निर्णय पर पूरी तरह से अवलंबन करते हुए दीवानी पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने में गलती की है। खंड को वैध ठहराने के लिए लागू सभी तीन अनिवार्य मानदंड तत्काल अपीलों में पूरे किए गए हैं। हम प्रत्येक लागू अंग के लिए संक्षिप्त कारण निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं।
29. प्रथम, अनुबंध अधिनियम की धारा 28 अनन्य क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों पर रोक नहीं लगाती है। जिस पर रोक लगाई गई है, वह किसी भी पक्ष को कानूनी मंच पर जाने से पूर्णतः प्रतिबंधित करना है। कानूनी निर्णय का अधिकार किसी भी पक्ष से अनुबंध के माध्यम से छीना नहीं जा सकता है, बल्कि पक्षों की सुविधा के लिए इसे कुछ न्यायालयों को सौंपा जा सकता है। वर्तमान विवाद में, यह प्रावधान कर्मचारी के कानूनी दावे को आगे बढ़ाने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि कर्मचारी को केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के समक्ष ही उन दावों को आगे बढ़ाने तक सीमित करता है।
30. दूसरे, न्यायालय के पास पहले से ही ऐसे कानूनी दावे पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यह इस तथ्य से संबंधित है कि कोई अनुबंध किसी ऐसे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता जिसके पास पहले से ऐसा अधिकार क्षेत्र न हो। इस मुद्दे को तय करने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 20 की व्याख्या आवश्यक है। इस मामले में, यह देखते हुए कि राकेश और दीप्ति को नियुक्त करने का निर्णय मुंबई में लिया गया था, राकेश के पक्ष में नियुक्ति पत्र मुंबई से जारी किया गया

था, रोजगार समझौता मुंबई से भेजा गया था, राकेश और दीप्ति की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय मुंबई में लिया गया था और सेवा समाप्ति पत्र मुंबई से भेजे गए थे, हम आश्वस्त हैं कि मुंबई के न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र है।

31. अंत में, अनुबंध में उल्लिखित खंड ने "अनन्य" शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को वर्जित कर दिया है। *एबीसी लैमिनेट* (उपरोक्त) के उद्धरण का संदर्भ उपयोगी हो सकता है, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

अनुतोष

32. इसलिए, एचडीएफसी बैंक का यह दावा जायज है कि वाद मुंबई के उचित न्यायालय में दायर किए जाने चाहिए थे।
33. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने विधि के बिंदु पर एचडीएफसी बैंक के पक्ष में सही निर्णय देते हुए भी एक मौलिक त्रुटि की है। इसने एचडीएफसी बैंक के आवेदन को दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ है कि वाद अस्वीकृत हो गया है। चूंकि मुंबई की न्यायालयों को राकेश द्वारा उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार है और उनका वाद अन्यथा नियम 11 के किसी भी खंड के लागू होने पर अस्वीकृत होने योग्य नहीं है, इसलिए पटना उच्च न्यायालय के लिए उचित प्रक्रिया यह होती कि वह विचारण न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 10 के तहत वाद को राकेश को वापस करने का निर्देश देता ताकि वह इसे मुंबई की सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। विचारण न्यायालय को वाद को राकेश को वापस करने और नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार पृष्ठांकन करने का निर्देश देते हुए, हम उन्हें मुंबई की सक्षम न्यायालय में ऐसा वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान

करते हैं।

34. यदि राकेश मुंबई की किसी सक्षम न्यायालय में नया वाद दायर करना चाहता है, तो ऐसे मामले में उसे वाद वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अपने द्वारा दायर किया गया वाद वापस ले सकता है।
35. जहाँ तक दीप्ति द्वारा दायर वाद का संबंध है, शिकायत को मुंबई की न्यायालयों में पेश करने के लिए उसे वापस करना होगा। वैकल्पिक रूप से, वह अपना लंबित वाद वापस ले सकती है और मुंबई की एक सक्षम न्यायालयों में एक नया वाद दायर कर सकती है।
36. राकेश और दीप्ति द्वारा संबंधित मैदानों में की गई दलीलों और प्रार्थनाओं से भी हमने देखा है कि वे दोषपूर्ण हैं। हम उन्हें अपनी-अपनी दलीलों में संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता देते हैं। यदि इस संबंध में आवेदन किए जाते हैं, तो विचारण न्यायालयें अपने विवेक से उसमें प्रार्थना की अनुमति दे सकती हैं। यदि नए वाद लगाए जाते हैं, तो यह स्वतंत्रता काम करना बंद कर देगी।
37. यदि नए वाद दायर किए जाते हैं, तो राकेश और दीप्ति अपनी दलीलों में उन आधारों का अनुरोध कर सकते हैं जिन पर दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 6 के संदर्भ में परिसीमा विधि से छूट का दावा किया जाता है।

निष्कर्ष

38. पटना उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश की ऊपर उल्लिखित सीमा तक पुष्टि की जाती है और मुख्य अपील को खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, संबंधित अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।
39. हम स्पष्ट करते हैं कि विवादों के गुण-दोषों की जाँच नहीं की गई है और सभी मुद्दे

खुले रखे गए हैं।

40. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: मामलों का निपटारा किया गया।

* निर्णय-सार लेखन: निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।